भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 244
सोमवार, 16 मार्च, 2026 (25 फाल्गुन 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाईअड्डे के विस्तार की योजना

***244. श्री खीरू महतो:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रांची-बोकारो हवाईअड्डे के विस्तार के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"हवाईअड्डे के विस्तार की योजना" के संबंध में श्री खीरू महतो द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2026 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): हवाईअड्डों का विस्तार और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा यह प्रक्रिया समय-समय पर भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक सरोकारों, यातायात की माँग/ऐसे हवाईअड्डों से/हवाईअड्डों के लिए परिचालन करने हेतु एयरलाइनों की इच्छा के आधार पर निष्पादित की जाती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने राँची हवाईअड्डे की क्षमता में वृद्धि करने के लिए समानांतर टैक्सी ट्रैक (पीटीटी), रैपिड एग्जिट ट्रैक (आरईटी) के निर्माण और मौजूदा टर्मिनल भवन के पुनर्विन्यास का कार्य शुरू किया है। हवाईअड्डा परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरियों की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के स्वामित्व वाले बोकारो हवाईअड्डे की क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-'उड़ान') के तहत विकास के लिए पहचान की गई है। हवाईअड्डा अवसंरचना के विकास के लिए 78.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

*****